

करेंट अफेयर्स

उत्तराखंड

(संग्रह)



जून
2025

Drishti, 641, First Floor,
Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry: +91-87501-87501
Email: care@groupdrishti.in

अनुक्रम

उत्तराखंड	3
☞ फूलों की घाटी	3
☞ 20वाँ गवर्नर कप गोल्फ टूर्नामेंट-2025	4
☞ उत्तराखंड में राज्य सहायता मिशन पर क्षेत्रीय कार्यशाला	5
☞ उत्तराखंड में रणनीतिक सलाहकार समिति	6
☞ उत्तराखंड में बेली ब्रिज	7
☞ उत्तराखंड में हिमालयी चमगादड़ की नई प्रजाति मिली	10
☞ गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान	11
☞ जनगणना-2027 की अधिसूचना जारी	12
☞ उत्तराखंड की पहली योग नीति	13
☞ प्रोजेक्ट एलीफेंट की संचालन समिति की बैठक	14

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



उत्तराखंड

फूलों की घाटी

चर्चा में क्यों ?

1 जून, 2025 उत्तराखंड में **फूलों की घाटी** को पर्यटकों के लिये आधिकारिक रूप से खोल दी गई, जिससे इसकी वार्षिक चार महीने की यात्रा अवधि की शुरुआत हो गई।

मुख्य बिंदु

- ❖ **फूलों की घाटी के बारे में:**
 - यह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है और **नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व** के भीतर स्थित है।
 - यह घाटी 87 वर्ग किलोमीटर में फैली है और समुद्र तल से 3,600 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है।
- ❖ **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:**
 - इस घाटी का पश्चिमी दुनिया से पहला परिचय वर्ष 1931 में हुआ, जब ब्रिटिश पर्वतारोही **फ्रैंक एस. स्माइथ**, **एरिक शिप्टन** और **आर. एल. होल्ड्सवर्थ** ने माउंट कामेट से लौटते समय इसे खोजा।
 - स्माइथ की वर्ष 1938 में प्रकाशित पुस्तक “**फूलों की घाटी**” ने इसे वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई।
- ❖ **वनस्पति और जीव-जंतु:**
 - यह घाटी सैकड़ों प्रकार के पुष्पों के लिये प्रसिद्ध है, जिनमें प्रमुख हैं— **ऑर्किड**, **पॉपी**, **प्रिमुला**, **गेंदा**, **गुलबहार** और **एनिमोन**।
 - यहाँ **ब्रह्मकमल** जैसे दुर्लभ व पवित्र पुष्प भी खिलते हैं, जो धार्मिक अनुष्ठानों में अर्पित किये जाते हैं।
 - यह क्षेत्र पारंपरिक उपचार पद्धतियों में प्रयुक्त **औषधीय पौधों और जड़ी-बूटियों** का भी प्रमुख भंडार है।
 - यहाँ के प्रमुख वन्य जीव हैं— **हिम तेंदुआ**, **हिमालयी वीजल**, **काला भालू**, **लाल लोमड़ी**, **धूसर लंगूर**, **उड़ने वाली गिलहरी** और **लाइम बटरफ्लाई** समेत कई प्रजातियों की तितलियाँ।
- ❖ **प्राकृतिक विशेषताएँ:**
 - घाटी में अल्पाइन घास के मैदान, झरते हुए जलप्रपात, **हिमानी** धाराएँ और घने वन देखने को मिलते हैं।
 - यह घाटी **ज़ास्कर और ग्रेटर हिमालय पर्वत** शृंखलाओं के बीच स्थित एक संक्रमणीय क्षेत्र (transition zone) में है।
- ❖ **संरक्षण प्रयास:**
 - पारिस्थितिकीय क्षरण की आशंका को देखते हुए, इसे वर्ष 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया।
 - वर्ष 1988 में इसे नंदा देवी **जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र** में शामिल किया गया और पर्यटन को कड़े नियंत्रणों के तहत धीरे-धीरे पुनः शुरू किया गया।
 - इसकी असाधारण सुंदरता और **जैवविविधता** को देखते हुए वर्ष 2005 में इसे **UNESCO** द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



♦ सांस्कृतिक महत्त्व:

- यह घाटी हिंदू पौराणिक परंपराओं में आध्यात्मिक महत्त्व रखती है और पारंपरिक रूप से भोटिया जनजाति द्वारा बसाई जाती रही है।
- यहाँ पाए जाने वाले पवित्र पुष्प, विशेषकर ब्रह्मकमल, को धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष स्थान प्राप्त है।

20वाँ गवर्नर कप गोल्फ टूर्नामेंट-2025

चर्चा में क्यों ?

राजभवन गोल्फ क्लब, नैनीताल द्वारा आयोजित 20वाँ गवर्नर कप गोल्फ टूर्नामेंट, 1 जून 2025 को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

- ♦ उत्तराखंड के राज्यपाल ने विभिन्न श्रेणियों में विजेताओं और उपविजेताओं को पुरस्कार प्रदान किये।

मुख्य बिंदु

♦ टूर्नामेंट के बारे में:

- यह टूर्नामेंट 30 मई से 1 जून 2025 तक तीन दिनों तक नैनीताल, उत्तराखंड में आयोजित किया गया था।
- इस आयोजन में भारत के विभिन्न राज्यों से कुल 177 गोल्फ खिलाड़ियों ने भाग लिया।

♦ महत्त्व:

- बच्चों, युवाओं और छात्रों को गोल्फ में रुचि लेने के लिये प्रोत्साहित करने के लिये राजभवन गोल्फ कोर्स 2024 में खोला गया।
- खेल में महिला खिलाड़ियों और युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिये विशेष प्रयास किये गए हैं।

♦ 2025 के विजेता:

वर्ग	विजेता
सुपर वेटेरेन ग्राॅस श्रेणी	कर्नल एस.सी. गुप्ता
महिला वर्ग	सृष्टि धन
ग्राॅस श्रेणी	ज़फर इकबाल
नेट श्रेणी (15-17 आयु वर्ग)	अमायरा बजाज
अमैच्योर श्रेणी (12-14 आयु वर्ग)	समृद्ध चंद ठाकुर

राज भवन गोल्फ क्लब, नैनीताल

- ♦ नैनीताल में राजभवन गोल्फ क्लब की स्थापना वर्ष 1926 में गवर्नमेंट हाउस एस्टेट के हिस्से के रूप में की गई थी।
- ♦ यह कोर्स नैनीताल के पर्वतीय क्षेत्र में समुद्र तल से 6,700 से 7,000 फीट की ऊँचाई पर हरे-भरे, मिश्रित वनों में स्थित है।
- ♦ राज भवन गोल्फ क्लब का एक समृद्ध ऐतिहासिक विरासत है और इसे पूरे भारत में गोल्फ खिलाड़ियों के लिये एक प्रमुख गंतव्य माना जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



उत्तराखंड में राज्य सहायता मिशन पर क्षेत्रीय कार्यशाला

चर्चा में क्यों ?

नीति आयोग ने उत्तराखंड सशक्तीकरण एवं परिवर्तन संस्थान (सेतु) आयोग के सहयोग से देहरादून में राज्य सहायता मिशन (SSM) के अंतर्गत एक दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की।

नीति आयोग

(राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था)

इतिहास- योजना आयोग

वर्ष 1950 में निवेश संबंधी गतिविधियों को निर्देशित करने हेतु स्थापित

नीति आयोग की संरचना

अध्यक्ष

प्रधानमंत्री

शासी मंत्रिपरिषद्

CMS (राज्य) और उपराज्यपाल (VTS)

क्षेत्रीय परिषदें

आवश्यकतानुसार गठित, जिसमें क्षेत्र के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल शामिल होते हैं

1 जनवरी, 2015 को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित

सदस्य

पूर्णकालिक

अंशकालिक सदस्य

अधिकतम 2, क्रमिक, महत्वपूर्ण संस्थानों से

पदेन सदस्य

अधिकतम 4 मंत्रिपरिषद् से, प्रधानमंत्री द्वारा नामित

विशेष आमंत्रितकर्ता

अनुभवी, विशेषज्ञ, डोमेन ज्ञान वाले अयासकर्ता

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

निश्चित कार्यकाल के लिये प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त (सचिव रैंक)

सचिवालय

आवश्यकतानुसार

उद्देश्य

- सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना
- विश्वसनीय योजनाओं के निर्माण हेतु तंत्र विकसित करना (ग्रामीण स्तर पर)
- आर्थिक रणनीति और नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी हितों को बढ़ावा
- सुभेद्य वर्गों पर विशेष ध्यान
- प्रमुख हितधारकों, नेशनल-इंटरनेशनल थिंक टैंक, शोध संस्थानों के बीच साझेदारी के लिये सलाह और प्रोत्साहन प्रदान करना
- ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता सहायता प्रणाली का निर्माण
- अंतर-क्षेत्रीय और अंतर-विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु मंच प्रदान करना
- अत्याधुनिक संसाधन केंद्र (state-of-the-art Resource Centre) बनाए रखना

नीति आयोग बनाम योजना आयोग

नीति आयोग	योजना आयोग
यह एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है।	यह गैर-संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता था।
इसमें व्यापक विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं।	इसमें सीमित विशेषज्ञता थी।
प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त सचिवों को CEO के रूप में जाना जाता है।	सचिवों को सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया जाता था।
यह योजना के 'बॉटम-अप' दृष्टिकोण पर केन्द्रित है।	इसने 'टॉप-डाउन' दृष्टिकोण का अनुसरण किया।
इसके पास नीतियाँ लागू करने का अधिकार नहीं है।	राज्यों पर नीतियों को लागू किया और अनुमोदित परियोजनाओं के साथ धन का आवंटन किया।
इसके पास निधि आवंटित करने का अधिकार नहीं है, जो वित्त मंत्री में निहित है।	इसे मंत्रालयों और राज्य सरकारों को निधि आवंटित करने का अधिकार था।

प्रमुख पहलें

- सतत् विकास लक्ष्य (SDG) इंडिया इंडेक्स
- अटल इनोवेशन मिशन
- ई-अमृत पोर्टल (इलेक्ट्रिक वाहन)
- सुशासन सूचकांक
- भारत नवाचार सूचकांक
- आकांक्षी जिला कार्यक्रम
- 'मेथनॉल अर्थव्यवस्था' कार्यक्रम

प्रमुख पहलें

- राज्यों को विवेकाधीन निधि प्रदान करने का अधिकार नहीं
- केवल एक सलाहकार निकाय
- निजी या सार्वजनिक निवेश को प्रभावित करने में कोई भूमिका नहीं
- संगठन का राजनीतिकरण
- सकारात्मक बदलाव लाने के लिये अपेक्षित शक्ति (Requisite Power) का अभाव



दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



मुख्य बिंदु

♦ क्षेत्रीय कार्यशाला के बारे में:

- यह कार्यशाला **राज्य सहायता मिशन (SSM)** के अंतर्गत आयोजित शृंखला की पहली कार्यशाला थी, जिसका उद्देश्य **राज्य परिवर्तन संस्थानों (SIT)** के माध्यम से नीति आयोग तथा राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के बीच संरचित सहयोग को बढ़ावा देना था।
- कार्यशाला का उद्देश्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को एक साथ लाकर **SSM** पहल पर अनुभव साझा करना, सहकर्मि शिक्षा को बढ़ावा देना और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये सहयोग बढ़ाना था।
- इसमें राज्य के विकास को गति देने तथा राज्य के विज्ञान को आकार देने में **SIT** की भूमिका पर प्रकाश डाला गया।

♦ राज्य सहायता मिशन (SSM):

- इस मिशन के अंतर्गत, नीति आयोग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को क्षमता निर्माण तथा राज्य परिवर्तन संस्थानों (SIT) की स्थापना में सहायता प्रदान करता है।
- इसका उद्देश्य राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप वर्ष 2047 तक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को उनके सामाजिक-आर्थिक विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करना है।
 - इस मिशन को 2022-23 से 2024-25 की अवधि के लिये 237.5 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी प्रदान की गई है।
- मिशन के क्रियान्वयन हेतु नीति आयोग में एक राज्य आर्थिक एवं परिवर्तन इकाई (सेतु) का गठन किया गया है।
 - संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी (मिशन निदेशक) की अध्यक्षता वाली इस इकाई में निदेशक, सहायक निदेशक, नवाचार प्रमुख तथा युवा पेशेवरों की एक टीम सम्मिलित है।
- SSM, सतत विकास लक्ष्यों (SDG)** के स्थानीयकरण प्रयासों को सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध होगा, जिससे **बहुआयामी गरीबी** को कम करने में मदद मिलेगी।

उत्तराखंड में रणनीतिक सलाहकार समिति

चर्चा में क्यों?

उत्तराखंड के **राज्यपाल** लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) ने नवाचार और प्रभावी कार्यान्वयन पर एक रणनीतिक सलाहकार समिति के गठन को मंजूरी दे दी है।

- इसके अलावा, **मुख्यमंत्री** पुष्कर सिंह धामी ने सामाजिक विकास, कौशल निर्माण और तकनीकी नवाचार को आगे बढ़ाने के लिये तीन प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किये।

मुख्य बिंदु

- रणनीतिक सलाहकार समिति: शासन नवाचार और प्रभावी कार्यक्रम कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिये **मुख्यमंत्री** की अध्यक्षता में।
- टाटा ट्रस्ट के साथ त्रिपक्षीय समझौता: **जल प्रबंधन**, पोषण, **टेलीमेडिसिन**, ग्रामीण आजीविका और **हरित ऊर्जा** पर केंद्रित 10 वर्षीय साझेदारी।
- नैसकॉम के साथ कौशल विकास समझौता: उत्तराखंड को एक तकनीकी कौशल केंद्र के रूप में स्थापित करेगा, जिसमें **AI**, डाटा विज्ञान, **साइबर सुरक्षा** और पायथन में पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाएंगे।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ❖ **वाधवानी फाउंडेशन** के साथ समझौता: सरकारी कॉलेजों में 1.2 लाख छात्रों के लिये **AI-संचालित** व्यक्तित्व विकास और कौशल प्रशिक्षण को एकीकृत करना।

राज्यपाल

परिचय

- राज्यपाल भारत में किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जो राष्ट्रीय स्तर पर **राष्ट्रपति** के समान भूमिका निभाता है।
- उनका पद **भारतीय संविधान** के अनुच्छेद 153 से 162 के अंतर्गत परिभाषित है और वे दोहरी क्षमता में कार्य करते हैं:
 - ❑ संवैधानिक प्रमुख के रूप में, राज्य की **मंत्रिपरिषद** की सलाह से बंधे हुए।
 - ❑ संघ और राज्य सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में, **भारत के संघीय ढाँचे** के भीतर समन्वय सुनिश्चित करना।

नियुक्ति एवं कार्यकाल:

- भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त।
- 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, हालाँकि त्यागपत्र या बर्खास्तगी से इसे कम किया जा सकता है।
- वह भारतीय नागरिक होना चाहिये, कम-से-कम 35 वर्ष का होना चाहिये तथा किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिये।

शक्तियाँ एवं जिम्मेदारियाँ:

- कार्यकारी, विधायी और **विवेकाधीन शक्तियाँ** रखता है।
- राज्य शासन, कानून निर्माण और आपातकालीन प्रावधानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- राज्य में संवैधानिक विफलता की स्थिति में **अनुच्छेद 356** के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है।

उत्तराखंड में बेली ब्रिज

चर्चा में क्यों?

उत्तराखंड के मिलम गाँव के निवासियों को **हिमस्खलन** के कारण गौखा नदी पर बने **बेली ब्रिज** के क्षतिग्रस्त होने के कारण महत्वपूर्ण पहुँच संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

- ❖ **सीमा सड़क संगठन (BRO)** को क्षति की मरम्मत करने और पुल को जल्द से जल्द पुनः स्थापित करने के निर्देश दिये गए हैं।

मुख्य बिंदु

पुल की अवस्थिति:

- मिलम गाँव से लगभग 8 किमी. दूर स्थित बेली ब्रिज गाँव और चीन सीमा पर स्थित कई सुरक्षा चौकियों के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क प्रदान करता है।



दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



लगभग 400 निवासियों की आबादी वाला मिलम गाँव, **भारत-चीन सीमा** के पास स्थित **जोहार घाटी** में अंतिम बसा हुआ क्षेत्र है।

- 65 किमी. लंबा **मुनस्यारी-मिलम मार्ग** इन मौसमी आवागमन के दौरान निवासियों के लिये एकमात्र संपर्क मार्ग है।

❖ बेली ब्रिज के बारे में:

- बेली ब्रिज एक प्रकार का मॉड्यूलर पुल (modular bridge) है, जिसके सभी हिस्से पहले से बने होते हैं, इसलिये आवश्यकतानुसार उन्हें जल्दी से जोड़ा जा सकता है।
- इसका आविष्कार **द्वितीय विश्व युद्ध** के दौरान ब्रिटिश सिविल इंजीनियर डोनाल्ड कोलमैन बेली (Donald Coleman Bailey) द्वारा किया गया था।
- इस पुल की प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं: मॉड्यूलर डिजाइन, परिवहन में आसानी, उच्च भार वहन क्षमता और विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में अनुकूलन क्षमता।
- बेली ब्रिजों को विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण वातावरण में त्वरित संयोजन के लिये डिजाइन किया गया है, जिसके लिये न तो भारी मशीनरी की आवश्यकता होती है और न ही उन्नत निर्माण तकनीक की।
- भारतीय सशस्त्र बलों को बेली ब्रिज का डिजाइन अंग्रेजों से विरासत में मिला था। इसे वर्ष 1971 के **भारत-पाक युद्ध** में और वर्ष 2021 की **उत्तराखंड बाढ़** जैसी आपदाओं में राहत कार्यों के दौरान प्रयोग में लाया गया था।

हिमस्खलन

❖ परिचय:

- हिमस्खलन अथवा हिमधाव (Avalanche) पर्वतीय ढलानों पर बर्फ, बर्फीले टुकड़ों तथा मलबे का तीव्र गति से नीचे की ओर बहना होता है। इसमें प्रायः मिट्टी, चट्टानें तथा मलबा भी शामिल होता है, जिससे भारी विनाश होता है।
- दिसंबर से अप्रैल के बीच हिमस्खलन का खतरा अधिक रहता है, क्योंकि इस अवधि में शीत ऋतु में भारी **हिमपात** (बर्फ का संचय) और **वसंत ऋतु** में हिम-स्तरों के कमजोर होने (हिम परतों का विगलन होना) की घटनाएँ होती हैं।

❖ प्रकार:

- अटूट हिम अवधाव (Loose Snow Avalanche):** यह एक एकल बिंदु से शुरू होता है, जहाँ हिम का आबंध सुदृढ़ नहीं होता, हिम के कणों के गिरने के साथ इसमें प्रतिलोमित V आकार में विस्तार होता है तथा अपेक्षाकृत कम मात्रा और गति के कारण यह कम संकटपूर्ण होता है।
- स्लैब हिमस्खलन (Slab Avalanche):** किसी संसक्त हिम पट्ट का अंतर्निहित परतों से टूटकर अलग होना स्लैब हिमस्खलन कहलाता है, जिसकी गति प्रायः 50 से 100 किमी/घंटा तक होती है और यह भीषण विनाश का कारण बनता है।
- ग्लाइडिंग हिमस्खलन (Gliding Avalanche):** इसमें हिम पुंज का घास अथवा चट्टान जैसी समान सतह से नीचे की ओर फिसलन होता है, जिससे इसमें विभंजन होता है और यह स्थिर हिम खंड से अलग हो जाता है।
- आर्द्र-हिम अवधाव (Wet-Snow Avalanche):** आर्द्र-हिम हिमस्खलन स्वाभाविक रूप से **तापमान** या **वर्षा में बढ़ोतरी** के कारण होता है, क्योंकि विगलित हिम के जल से हिम परत का आबंध कमजोर हो जाता है।

सीमा सड़क संगठन (BRO)

- देश के **उत्तरी और पूर्वोत्तर सीमावर्ती क्षेत्रों** में सड़कों के नेटवर्क के तीव्र विकास के समन्वय के लिये वर्ष 1960 में सीमा सड़क संगठन (BRO) की स्थापना की गई थी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



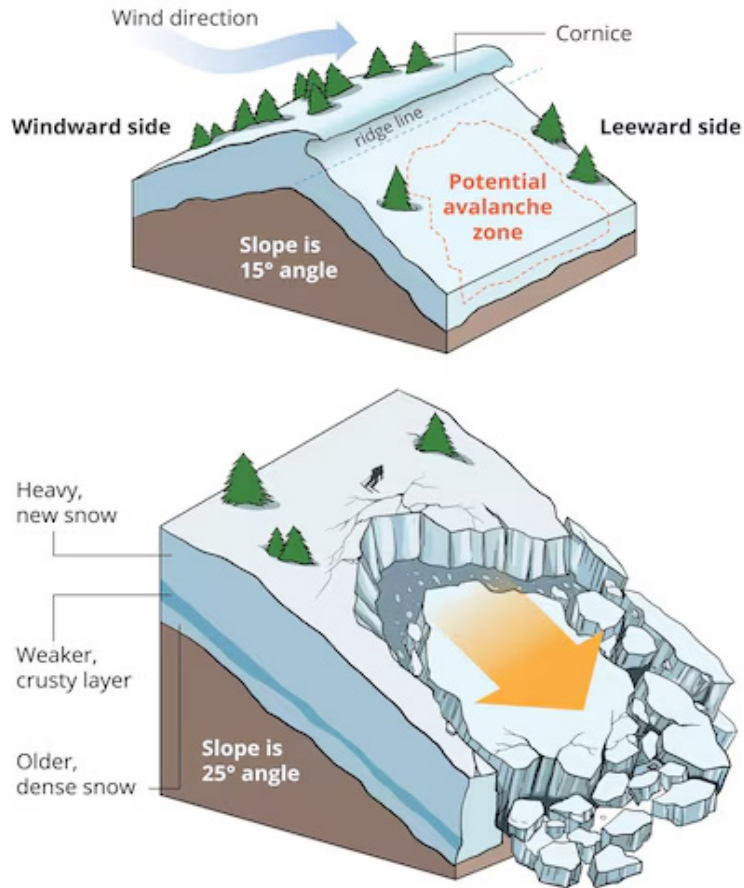
दृष्टि लर्निंग
ऐप



● यह संगठन रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।

- ◆ BRO ने अब अपना कार्यक्षेत्र हवाई पट्टियों, भवन परियोजनाओं, रक्षा संबंधी निर्माण तथा सुरंग निर्माण तक विस्तारित कर लिया है।
- ◆ केंद्र सरकार ने सीमा सड़क विकास बोर्ड (BRDB) की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री तथा उपाध्यक्ष रक्षा मंत्री होते हैं।

AVALANCHE ANATOMY



दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



उत्तराखंड में हिमालयी चमगादड़ की नई प्रजाति मिली

चर्चा में क्यों ?

भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में किये गए एक अध्ययन में विज्ञान के लिये एक नई **चमगादड़ प्रजाति**, हिमालयन लॉन्ग-टेल्ड मायोटिस (*मायोटिस हिमालयकस*) का पता चला है, जो उत्तराखंड में पाई गई है।

❖ इससे पहले इसकी पहचान वर्ष 1998 में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हुई थी।

मुख्य बिंदु

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष और निहितार्थ

- ❖ अध्ययन के बारे में: भारतीय वैज्ञानिकों ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के **पश्चिमी हिमालय** क्षेत्र में सर्वेक्षण के दौरान वर्ष 2017 तथा 2021 के बीच 29 चमगादड़ प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया।
- ❖ नई चमगादड़ प्रजाति: उत्तराखंड के **केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य** में पाए जाने वाले हिमालयन लॉन्ग-टेल्ड मायोटिस को जूटाक्सा जर्नल में औपचारिक रूप से एक नई प्रजाति के रूप में वर्णित किया गया है।
 - ⦿ इसके साथ ही भारत में **चमगादड़ प्रजातियों** की कुल संख्या 135 हो गई है।
- ❖ ज्ञात प्रजातियों का विस्तार: ईस्ट एशियन फ्री-टेल्ड बैट (*Tadarida insignis*), जिसे पहले यूरोपीय प्रजाति समझा जाता था, को पहली बार भारत में स्पष्ट रूप से पहचाना गया है।
 - ⦿ यह प्रजाति **चीन और ताइवान** से लगभग 2,500 किमी दूर भारत के पश्चिमी हिमालय में दर्ज की गई है।
- ❖ बाबू पिपिस्ट्रैल की वैध प्रजाति के रूप में पुष्टि:
 - ⦿ अध्ययन ने बाबू पिपिस्ट्रैल (*पिपिस्ट्रैलस बाबू*) को जावा पिपिस्ट्रैल (*पी. जावानिकस*) से अलग एक वैध प्रजाति के रूप में पुनर्स्थापित किया गया है।
 - ⦿ पहले इसे रूपात्मक समानताओं के कारण समानार्थी माना जाता था, लेकिन अब यह पुष्टि हो गई है कि बाबू पिपिस्ट्रैल **पाकिस्तान, भारत और नेपाल में पाया जाता है।**
- ❖ भारत में पहली बार रिकॉर्ड:
 - ⦿ इस अध्ययन में निम्नलिखित प्रजातियों की भारत में पहली बार नमूना आधारित पुष्टि की गई है:
 - 🔍 सावीज़ पिपिस्ट्रैल (*Hypsugo savii*)
 - 🔍 जापानी ग्रेटर हॉर्सशू बैट (*Rhinolophus nippon*)
- ❖ प्रमुख प्रजातियाँ एवं संरक्षण:
 - ⦿ प्रमुख प्रजातियों में ब्लैंडफोर्ड का फलाहारी चमगादड़, जापानी और चीनी हॉर्सशू बैट्स, नेपाली व्हिस्कर्ट बैट, मंडेल्ली का माउस-ईयर्ड बैट, कश्मीर गुफा मायोटिस, चॉकलेट पिपिस्ट्रैल एवं ईस्टर्न लॉन्ग-विंग्ड बैट शामिल थे।
 - ⦿ **भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI)** के अनुसार यह शोध भारत में विशेषकर पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र में लघु स्तनधारी विविधता के संरक्षण तथा प्रलेखन को मजबूती प्रदान करेगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI)

- ❖ ZSI पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का एक अधीनस्थ संगठन है और इसकी स्थापना वर्ष 1916 में एक राष्ट्रीय पशु सर्वेक्षण एवं संसाधनों की खोज केंद्र के रूप में की गई थी, जिससे देश की असाधारण रूप से समृद्ध पशु विविधता के बारे में ज्ञान में वृद्धि हुई।
- ❖ इसका मुख्यालय कोलकाता में है और देश के विभिन्न भौगोलिक स्थानों पर इसके 16 क्षेत्रीय केंद्र स्थित हैं।

गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान

चर्चा में क्यों ?

उत्तरकाशी जिले के निवासियों ने भागीरथी पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र में स्थित गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के अंदर एक नए अपशिष्ट भस्मक (waste incinerator) को लेकर केंद्र सरकार के समक्ष चिंता व्यक्त की है।

मुख्य बिंदु

- ❖ गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान:
 - ⦿ इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1989 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल 1,553 वर्ग किलोमीटर है तथा इसकी ऊँचाई 7,083 मीटर है। इसमें विविध भू-भाग शामिल हैं।
 - ⦿ यह पार्क गौमुख-तपोवन ट्रेक का घर है, जो इस क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय ट्रेकिंग मार्गों में से एक है।
 - ⦿ गंगा नदी का उद्गम स्थल, गंगोत्री ग्लेशियर पर स्थित गौमुख, इसी पार्क के अंदर स्थित है।
 - ⦿ वनस्पति: यह पार्क घने शंकुधारी वनों से आच्छादित है, जो अधिकांशतः समशीतोष्ण प्रकृति के हैं। यहाँ की सामान्य वनस्पतियों में चीड़, देवदार, फर, स्प्रूस, ओक तथा रोडोडेंड्रोन शामिल हैं।
 - ⦿ जीव-जंतु: इस पार्क में विभिन्न दुर्लभ तथा संकटग्रस्त प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जैसे – भारल (नीली भेड़), काला भालू, भूरा भालू, हिमालयन मोनाल, हिमालयन स्नोकोक, हिमालयन तहर, कस्तूरी मृग तथा हिम तेंदुआ।
- ❖ भागीरथी पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र (ESZ):
 - ⦿ वर्ष 2012 में पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) द्वारा एक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से गौमुख से उत्तरकाशी तक भागीरथी नदी के विस्तार के साथ 4,179.59 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) घोषित किया गया था।
 - ⦿ ESZ वे क्षेत्र हैं जिन्हें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत औद्योगिक प्रदूषण तथा अनियमित विकास से संरक्षित करने के लिये नामित किया जाता है।
- ❖ CPCB द्वारा उद्योग वर्गीकरण में संशोधन:
 - ⦿ अप्रैल माह में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने संशोधित उद्योग वर्गीकरण के अंतर्गत एक नई नीली श्रेणी (Blue Category) शुरू की।
 - ⦿ इस श्रेणी में आवश्यक पर्यावरणीय सेवाएँ शामिल की गई हैं, जैसे- अपशिष्ट से ऊर्जा (waste-to-energy) संयंत्र तथा शहरी अपशिष्ट प्रबंधन हेतु एकीकृत सैनिटरी लैंडफिल।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



❖ कानूनी तथा पर्यावरणीय चिंताएँ:

- ❶ कानून का उल्लंघन: प्रस्तावित भस्मक का स्थान पर्यावरण संरक्षण के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, क्योंकि संवेदनशील क्षेत्रों में उद्योगों पर प्रतिबंध है।
- ❷ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016: इन नियमों के अनुसार, पर्वतीय क्षेत्रों में लैंडफिल का निर्माण सख्त वर्जित है तथा अपशिष्ट को मैदानी क्षेत्रों में उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित किया जाना चाहिये।
- ❸ जैवविविधता पर प्रभाव: गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी हिमालय जैवविविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा है, जो अद्वितीय वनस्पतियों और जीवों से समृद्ध है।
 - ❶ ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में भस्मक की उपस्थिति से पारिस्थितिकी क्षरण का खतरा बढ़ जाता है।
- ❹ सार्वजनिक विरोध: स्थानीय कार्यकर्ताओं तथा निवासियों ने गंगोत्री क्षेत्र के संवेदनशील पारिस्थितिक संतुलन को उजागर करते हुए कड़ी आपत्ति जताई है।
 - ❶ उनका तर्क है कि हिमालय में इस प्रकार की सुविधा की स्थापना से क्षेत्र की जैवविविधता को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है, जो अपने विशिष्ट तथा संवेदनशील पर्यावरण के कारण पहले से ही असुरक्षित है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

- ❖ CPCB एक वैधानिक संगठन है और इसका गठन 1974 में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत किया गया था।
- ❖ CPCB को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत शक्तियाँ एवं कार्य भी सौंपे गए।
- ❖ यह एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में कार्य करता है तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के संबंध में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएँ भी प्रदान करता है।

जनगणना-2027 की अधिसूचना जारी

चर्चा में क्यों ?

केंद्र सरकार ने जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 3 के तहत वर्ष 2027 में दशकीय जनगणना के आयोजन को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया है।

- ❖ यह अधिसूचना मार्च 2019 के एक पूर्ववर्ती आदेश का स्थान लेती है, जिसमें शुरू में वर्ष 2021 में जनगणना के लिये कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें इसमें विलंब हुआ।

नोट: धारा 3 के अधीन, केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उन संपूर्ण राज्यक्षेत्रों या उनके किसी भाग में, जिन पर यह अधिनियम लागू होता है, जनगणना करने का अपना आशय घोषित कर सकती है, जब कभी वह ऐसा करना आवश्यक या वांछनीय समझे, तत्पश्चात् जनगणना की जाएगी।

मुख्य बिंदु

- ❖ अद्यतन जनगणना अनुसूची:
 - ❶ देश के अधिकांश भागों के लिये जनगणना की संदर्भ तिथि 1 मार्च, 2027 होगी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- हालाँकि, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे क्षेत्र, जो बर्फ और दुर्गम भू-भाग के कारण रसद संबंधी चुनौतियों का सामना करते हैं, 1 अक्टूबर, 2026 की पूर्व संदर्भ तिथि का पालन करेंगे।
- यह समायोजन इन क्षेत्रों में अधिक सटीक डाटा संग्रहण की अनुमति देता है।

जनगणना:

- भारतीय जनगणना देश की जनसंख्या पर जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक आँकड़ों का सबसे बड़ा स्रोत है।
- भारत की पहली समन्वित जनगणना वर्ष 1881 में भारत के तत्कालीन जनगणना आयुक्त डब्ल्यू.सी. प्लोडेन के अधीन हुई थी।
- इसने लगातार हर 10 वर्ष में विस्तृत सांख्यिकीय जानकारी उपलब्ध कराई है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1872 से हुई, जब भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पहली गैर-समकालिक जनगणना आयोजित की गई थी।

कानूनी ढाँचा और संस्थागत विकास:

- जनगणना अधिनियम, 1948 को जनगणना कार्यों के लिये कानूनी ढाँचा तैयार करने तथा जनगणना अधिकारियों की भूमिकाएँ परिभाषित करने के लिये अधिनियमित किया गया था।
 - यद्यपि यह अधिनियम कानूनी ढाँचा प्रदान करता है, लेकिन यह किसी विशिष्ट आवृत्ति को अनिवार्य नहीं करता, जिससे दशकीय पैटर्न एक संवैधानिक आवश्यकता न होकर एक परंपरा बन जाता है।
- मई 1949 में भारत सरकार ने जनसंख्या और जनसांख्यिकीय आँकड़ों के संग्रह को व्यवस्थित करने के लिये गृह मंत्रालय के अधीन एक स्थायी जनगणना संगठन की स्थापना की।
- बाद में महापंजीयक कार्यालय को जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 को क्रियान्वित करने का कार्य सौंपा गया, जिससे महत्वपूर्ण आँकड़ों को बनाए रखने में इसकी भूमिका का और विस्तार हुआ।

उत्तराखंड की पहली योग नीति

चर्चा में क्यों ?

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैण में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राज्य की पहली योग नीति का शुभारंभ किया।

- साथ ही गढ़वाल और कुमाऊँ क्षेत्रों में 'आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र' (Spiritual Economic Zones) के निर्माण की भी घोषणा की गई।

मुख्य बिंदु

योग नीति के बारे में:

- इसका उद्देश्य उत्तराखंड को योग और कल्याण की वैश्विक राजधानी के रूप में विकसित करना है।
- यह नीति 'हर घर योग, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य' की अवधारणा को बढ़ावा देती है, जिसमें केंद्र सरकार का सहयोग प्राप्त है।

वित्तीय प्रावधान:

- इस नीति के तहत योग और ध्यान केंद्रों की स्थापना के लिये अधिकतम 20 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी।
- योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित अनुसंधान गतिविधियों को अधिकतम 10 लाख रुपए तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



❖ कार्यान्वयन लक्ष्य:

- मार्च 2026 तक राज्य के सभी आयुष स्वास्थ्य और वेलेनेस केंद्रों पर योग सेवाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी।
- वर्ष 2030 तक राज्य में पाँच नए योग केंद्र विकसित किये जाएंगे।

❖ आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र:

- इन क्षेत्रों को आयुर्वेद, योग और आध्यात्मिक पर्यटन के लिये अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।
- इन क्षेत्रों के माध्यम से राज्य में नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
- यह पहल स्थानीय स्तर पर आजीविका के अवसर उपलब्ध कराकर पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन को रोकने में सहायक सिद्ध होगी।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

❖ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में:

- शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण के लिये योग के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा इसके अभ्यास के माध्यम से वैश्विक सद्भाव और शांति को बढ़ावा देने के लिये पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है।

❖ उद्गम और संयुक्त राष्ट्र की घोषणा:

- इसका प्रस्ताव भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र (2014) में रखा गया था, जिसके परिणामस्वरूप 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (IDY) घोषित किया गया।
 - ❏ पहला योग दिवस वर्ष 2015 में मनाया गया था, जिसकी थीम थी: "Yoga for Harmony and Peace" (सामंजस्य और शांति के लिये योग)।
 - ❏ वर्ष 2025 का विषय है "एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिये योग"।

❖ 21 जून का महत्त्व:

- यह तिथि ग्रीष्म अयनांत (Summer Solstice) के साथ संयोग रखती है, जो उत्तरी गोलार्द्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। योग परंपरा में यह दिन प्रकाश, ऊर्जा तथा आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक माना जाता है।

❖ वैश्विक मान्यता:

- यूनेस्को ने वर्ष 2016 में योग को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने योग को मानसिक और शारीरिक कल्याण और गैर-संक्रामक रोगों (NCDs) से निपटने के एक प्रभावी साधन के रूप में मान्यता दी है तथा इसे अपने वैश्विक कार्य योजना (2018-30) में शामिल किया है।
- वर्ष 2015 में भारत के युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय ने योग को एक 'प्राथमिकता' खेल अनुशासन के रूप में वर्गीकृत किया।

प्रोजेक्ट एलीफेंट की संचालन समिति की बैठक

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी (IGNFA) में आयोजित प्रोजेक्ट एलीफेंट की 21वीं संचालन समिति की बैठक में मानव-हाथी संघर्ष जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे के समाधान पर ध्यान केंद्रित किया गया।

- ❖ बैठक में संघर्ष प्रबंधन हेतु कार्य योजनाओं सहित चल रही पहलों की समीक्षा की गई तथा संरक्षण प्रयासों में स्थानीय समुदायों की भागीदारी पर जोर दिया गया।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



मुख्य बिंदु

♦ हाथी के बारे में:

- हाथी भारत का प्राकृतिक विरासत पशु है।
- इन्हें “कीस्टोन प्रजाति” माना जाता है, क्योंकि ये वन पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन तथा स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
 - ये अपनी असाधारण बुद्धि के लिये प्रसिद्ध हैं तथा इनका मस्तिष्क किसी भी स्थलीय प्राणी की तुलना में सबसे बड़ा होता है।
- भारतीय हाथी (*Elephas maximus*) मध्य एवं दक्षिणी पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी भारत, उत्तरी भारत तथा दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है।
- इसे भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में तथा वनस्पतियों और जीवों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) के परिशिष्ट-I में शामिल किया गया है।
- एशियाई हाथियों (भारतीय) को आवास क्षति, मानव-हाथी संघर्ष तथा अवैध शिकार के कारण IUCN रेड लिस्ट में लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

♦ प्रोजेक्ट एलीफेंट:

- प्रोजेक्ट एलीफेंट को भारत सरकार द्वारा वर्ष 1992 में एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ प्रारंभ किया गया था:
 - हाथियों, उनके आवास तथा गलियारों की सुरक्षा करना
 - मानव-हाथी संघर्ष के मुद्दों का समाधान करना
 - बंदी हाथियों का कल्याण सुनिश्चित करना
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इस योजना के अंतर्गत देश के प्रमुख हाथी क्षेत्रों वाले राज्यों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

♦ शिवालिक हाथी रिज़र्व, उत्तराखंड:

- इसकी स्थापना वर्ष 2002 में प्रोजेक्ट एलीफेंट पहल के एक भाग के रूप में की गई थी।
- यह भारत के हाथियों के सर्वाधिक घनत्व वाले क्षेत्रों में से एक है।
- इस रिज़र्व में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व तथा सोनानदी वन्यजीव अभयारण्य सहित अनेक संरक्षित क्षेत्र सम्मिलित हैं।

नोट:

- विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है ताकि जंगलों में एशियाई तथा अफ्रीकी हाथियों की संरक्षण स्थिति और उनके समक्ष उपस्थित चुनौतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके।
- वर्ष 2025 में यह समारोह कोयंबटूर, तमिलनाडु में आयोजित किया जाएगा, जहाँ हाथी संरक्षण में योगदान के लिये प्रतिष्ठित ‘गज गौरव’ पुरस्कार भी प्रदान किये जाएंगे।



दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025UPSC
क्लासरूम
कोर्सIAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्सदृष्टि लर्निंग
ऐप